Parliament House Annexe

3132. DR. VASANT KUMAR PANDIT: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the total cost at which the Parliament House Annexe was got constructed and the authority by which this decision was taken;

(b) when this building was completed and handed over to C.P.W.D. and what is its annual maintenance cost;

(c) whether Government received complaints of embezzlement in the construction of this building and if so, whether the same were got investigated and found true;

(d) whether it is also a fact that basement to first floor of the building is air conditioned and the rest on which the staff is accommodated is not air conditioned; and

(e) by what time the whole building is proposed to be made air conditioned and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) The booked expenditure upto end of March, 1977 is Rs. 3,73,29,506 including Department Charges). However, some bills are still outstanding. The total expenditure on the work is expected to be Rs. 3,75,00,000. Sanction for the amount was accorded by Lok Sabha Secretariat *vide* their letter No. 9/1/68-WG dated 19-8-1974.

(b) The building was completed on 15th December, 1975. Annual expenditure on maintenance is:—

Civil	..	Rs. 1,38,800
Horticulture	...	Rs. 70,303
Electrical	..	Rs. 1,82,706

(c) No, Sir.

(d) Yes, Sir.

(e) An additional estimate for Rs. 39.71 lakhs for air conditioning of the upper portions of the building has been submitted by Chief Engineer (Electrical), C.P.W.D. to Government for sanction. This is under examination.

स्लम प्रगृहों की किराया खरीद कीमत

3133. **श्री महीपाल** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह स्लम प्रगृहों की कीमत के बारे में 23 अगस्त, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1189 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण विंग ने स्लम प्रगृहों के किराया खरीद मूल्य के बारे में इस बीच कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो कालोनी-वार, विशेष रूप से रणजीत नगर कालोनी के लिए क्या मूल्य निर्धारित किया गया है, और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं, जब कि किराया खरीद आधार पर इन प्रगृहों को आवंटित करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां । कुछ मामलों में ।

(ख) रणजीत नगर कालोनी के लिए मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है उन कालोनियों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है जहां मूल्य निर्धारित कर दिये गये हैं ।

(ग) मूल्य का निर्धारण कई कारणों पर निर्भर करता है तथा अन्य कालोनियों के लिए मूल्य निर्धारित किया जा रहा है ।

Production of Food Grade Oil From Rice Bran

3134. SHRI G. Y. KRISHNAN: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration of Food Corporation of India for a plan to promote production of food grade oil in India from rice bran;

(b) whether it is also a fact that the Central Food Technological Research Institute (CFTRI) at Mysore has developed a process to prevent rice bran from becoming rancid; and

(c) if so, whether Government are satisfied with its programme and if so, further steps Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) By installing Rice Bran Stabilisers, FCI have succeeded in producing Bran oil with low Free Fatty Acid content in their Sembanarkoil Solvent Plant. This oil was sold to the Vanaspati Industry at a premium price compared to the price of Industrial grade oil. Further research, development and extension work is being planned in order to promote this technique.

डी० डी० ए० के हस्तांतरिक फ्लैटों के आबंटन के बारे में नई रीति

3135. **श्री रामनरेश कुशवाहा :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० डी० ए० फ्लैटों का आबंटन होने के पश्चात् परिस्थितियों से बाध्य होकर आबंटी व्यक्ति वे फ्लैट अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित करके दिल्ली से बाहर चले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी परिस्थितियों में नई नीति निर्धारित करके हस्तांतरित फ्लैटों को इस समय वहां रहने वाले व्यक्तियों के नाम आबंटित करने की कोई व्यवस्था कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण नियमों के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण के बने बनाये फ्लैटों का अन्तरण मूल आवन्टी के परिवार के सदस्यों को करने की अनुमति है तथा यदि आवंटी का अपना कोई परिवार न हो तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी को जिसकी परिभाषा हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम, 1956 में दी गई है । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ऐसे अन्तरण की अनुमति दे दी है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) मौजूदा नीति से हट जाना सरकार आवश्यक नहीं समझती ।

Rajasthan Canal Project

3136. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) when is the Rajasthan Canal Project expected to be completed and what will be its estimated total cost:

(b) why is its progress slow;

(c) whether the French or Iran Governments come forward to finance